



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17808 वर्ष 2026

अल्टमशआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद जी मिश्रा, कौशल कुमार पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना अकबराबाद, जिला अलीगढ़ में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 149 वर्ष 2026, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 2/11, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 और बीएनएस की धारा 325 के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 30.03.2026 से जेल में है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के मामले के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुसार, घटना की कथित तिथि और समय पर, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक नाले में गोमांस फेंक दिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ दिनों बाद, पुलिस द्वारा आवेदक को कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और मु.अ.सं. 152 वर्ष 2026 में उसका चालान कर दिया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामले में, आवेदक को इस न्यायालय की समान अधिकारिता वाली पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा आपराधिक इतिहास को भली-भांति स्पष्ट किया गया है। आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए.जी.ए. की परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की विषयवस्तु को देखने के बाद, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- अल्लमश को 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका वह आरोपी है, या जिसके घटित होने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनबद्ध पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (तदनुरूप बीएनएस की धारा 269) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तदनुरूप बीएनएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तदनुरूप बीएनएस की धारा 209) के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तदनुरूप बीएनएस की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

जून 9, 2026

ए.एन. मिश्रा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"